नईदुनिया

अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर चीनी उत्पादों के उच्च शुल्क का असर

हांगकांग

चीन से विभिन्न उत्पादों के आयात पर लगाए गए अमेरिकी उच्च शुल्कों का असर अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। चीन के लॉजिस्टिक्स एंड परचेजिंग फेडरेशन ने जारी किया गया आधिकारिक सर्वेक्षण में बताया है कि अप्रैल में उत्पादों के निर्यात ऑर्डर में गिरावट आई है। अमेरिकी प्रशासन ने चीनी उत्पादों पर 145 प्रतिशत तक का शुल्क लगाने का आदेश दिया था,

अप्रैल में उत्पादों के निर्यात ऑर्डर में गिरावट आई

जिसका प्रभाव अब उसके निर्यात पर दिखाई दे रहा है। वहीं चीन ने इसके जवाब में अमेरिकी उत्पादों पर 125 प्रतिशत तक का शुल्क लगाया है। इस परिस्थिति में आधिकारिक विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) ने 16 महीनों का सबसे निचला स्तर दर्शाते हुए मार्च में 49.0 पर पहुंच गया। वित्तीय सूचना समूह कैक्सिन ने भी एक निजी सर्वेक्षण के माध्यम से बताया कि पीएमआई कम होकर 50.4 पर पहुंच गया है। इस विचार को लेकर कि कैपिटल इकोनॉमिसस्ट ने कहा कि यह गिरावट व्यापक शुल्क के प्रभाव को दिखाती है, जो चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में आपूर्ति और मांग में वृद्धि धीमी रही, निर्यात में कमी आई और रोजगार में थोड़ी कमी आई। विनिर्माताओं ने भंडार कम करने की मांग की, रसद में देरी हुई और कीमतें दबाव में रहीं। निजी अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस वर्ष और अगले वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमान में भी कमी आई है। कैपिटल इकोनॉमिस्ट के अनुमान के मुताबिक, 2025 में अर्थव्यवस्था केवल 3.5 प्रतिशत बढ़ेगी। इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएफएफ) ने अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए भविष्य के लिए भी कमी के संकेत दिए हैं।

न्यूज ब्रीफ

बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का मुनाफा बढ़ा

मुंबई। शेयर बाजार में बजाज ग्रुप के दोनों बड़े नाम, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ने मुनाफे भरे नतीजे पेश कर दिए हैं। बजाज फाइनेंस ने अपने शेयरधारकों को 56 रुपये डिविडेंड और बोनस शेयर का ऐलान किया है। बजाज फाइनेंस का मुनाफा मार्च 2025 को समाप्त तिमाही में 16 प्रतिशत बढ़कर 3,940 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 3,402 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। इसके साथ ही, कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 44 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम डिविडेंड और 12 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का स्पेशल डिविडेंड भी घोषित किया है। विपक्ष में बजाज फिनसर्व लिमिटेड का मुनाफा मार्च 2025 को समाप्त चौथी तिमाही में 14 प्रतिशत बढ़कर 2,417 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने निदेशक मंडल की सिफारिश पर एक रुपये प्रति शेयर के 100 प्रतिशत लाभांश की सिफारिश की है। इससे कंपनी द्वारा घोषित कुल लाभांश 56 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा और शेयरधारकों को 4:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने का भी ऐलान किया गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने जलपोत निर्माण नीति को मंजूरी दी

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को जलपोत निर्माण, उनकी मरम्मत, पुनर्चक्रण के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए एक नीति मंजूर की है। जलपोत निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण नीति, 2025 के तहत इस क्षेत्र में सुविधाएं स्थापित करने वाली कॉरपोरेट संस्थाओं को पूंजीगत सब्सिडी, कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता और रियायती दरों पर या दीर्घकालिक पट्टे पर जमीन दी जाएगी।राज्य मंत्रिमंडल ने मुंबई में अपनी बैठक में नीति को मंजूरी दी।बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने कहा कि भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को जलपोत निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण के लिए एक प्रमुख केंद्र में बदलने का संकल्प लिया है।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में तेजी

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार शुल्क को लेकर बातचीत की प्रगति का संकेत दिया। उनकी घोषणा ने व्यापार समझौते को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी है। ट्रंप ने यह बयान मिशिगन में होने वाली एक रैली से पहले दिया।भारत उन पहले देशों में शामिल हो सकता है, जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करेगा व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि वह अफ्रीका दौरे की योजना बना रहे हैं और ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के साथ बातचीत करने वाले हैं। एक समाचार एजेंसी ने भारतीय सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया कि केंद्र सरकार अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में एक ऐसा लुभावना प्रस्ताव शामिल करने जा रही है, जिससे यह समझौता भविष्य में भी सुरक्षित बना रहे। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी अन्य व्यापारिक साझेदार को इससे बेहतर शर्तें न मिलें। यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जब रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सरकार फॉरवर्ड मोस्ट-फेवर्ड-नेशन क्लॉज शामिल करने पर विचार कर रही है, जिसे पहले के व्यापार समझौतों में केंद्र सरकार ने बहुत कम ही मंजूरी दी है। इस क्लॉज के तहत अमेरिका को यह सुविधा मिलेगी कि अगर भारत भविष्य में किसी और देश को बेहतर टैरिफ शर्तें देता है, तो वे शर्तें अपने आप अमेरिका पर भी लागू हो जाएंगी।बीते मंगलवार को अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट ने कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भारत उन पहले देशों में शामिल हो सकता है, जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करेगा। इसी सेंटीमेंट को अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने भी दोहराया।

गूगल असिस्टेंट को एआई वॉयस असिस्टेंट में बदलने की योजना

नई दिल्ली

अपने एआई मॉडल्स को गूगल अब और भी ज्यादा सर्विसेस और गैजेट्स में इंटीग्रेट करने पर ध्यान दे रहा है। गूगल ने इस साल के अंत तक गूगल असिस्टेंट को एक एआई वॉयस असिस्टेंट में बदलने की योजना बनाई है। कंपनी ने पहले ही जीमेल और गूगल फोटो जैसे ऐप्स में जेमिनी को शामिल कर लिया है, और अब इसे और भी डिवाइसों और सर्विसेस में लाने की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल ने हिंट दिया था कि वह स्मार्टवॉच में जेमिनी को इंटीग्रेट करने की योजना बना रहा है। अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने कंपनी की पहली तिमाही की अर्निंग कॉल के दौरान इन अटकलों की पुष्टि करते हुए कहा, हम मोबाइल डिवाइसेस पर गूगल असिस्टेंट को जेमिनी में अपग्रेड कर रहे हैं, और इस साल के अंत तक हम टैबलेट, कार और हेडफोन जैसी कनेक्टिविटी वाले डिवाइसों को भी अपग्रेड करेंगे। हालांकि गूगल का वियर ओएस अभी सबसे एडवांस्ड वॉच इंटरफेस नहीं है, फिर भी यह सैमसंग गैलेक्सी वॉच और वनप्लस वॉच जैसी प्रीमियम स्मार्टवॉच के मुकाबले एक पसंदीदा विकल्प बना हुआ है। स्मार्टवॉच में जेमिनी का इंटेग्रेशन एक बड़ा कदम होगा। अब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस साल के अंत तक का क्या मतलब है क्या गूगल अपने आई/ओ इवेंट के दौरान मई में या फिर दूसरी छमाही में नई पिक्सेल वॉच के लॉन्च के साथ यह घोषणा करेगा इसके अलावा, यह भी देखा जाएगा कि कैसे जेमिनी स्मार्टवॉच में सीमित स्टोरेज और प्रोसेसर के साथ काम करेगा ।

रेनॉल्ट कंपनी चेन्नई में नया डिजाइन स्टूडियो स्थापित करेगी

नई दिल्ली। हाल ही में रेनॉल्ट कंपनी ने भारतीय बाजार के लिए अपनी नई रणनीति का खुलासा किया, जिसमें चेन्नई में एक नया डिजाइन स्टूडियो स्थापित करना शामिल है। यह डिजाइन केंद्र यूरोप के बाहर रेनॉल्ट का सबसे बड़ा स्टूडियो होगा। इसके साथ ही, रेनॉल्ट की योजना अगले दो वर्षों में भारत में पांच नए मॉडल्स लॉन्च करने की है, जिसमें तीसरी पीढ़ी की डस्टर और इसका सात सीटों वाला वर्जन बिगस्टेर शामिल है। रेनॉल्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डस्टर और इसके तीन-रो वर्जन के लिए डीजल इंजन का उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि कंपनी आगामी एसयूवी मॉडल्स के लिए हाइब्रिड पावरट्रेन लाने की योजना बना रही है। में डिजाइनिंग स्टूडियो के उद्घाटन के दौरान, रेनॉल्ट इंडिया के सीईओ वेंकटराम ममिल्लापल्ले ने हाइब्रिड और सीएनजी विकल्पों के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि रेनॉल्ट भारतीय बाजार के लिए व्यावहारिक हाइब्रिड विकल्पों पर विचार कर रहा है, जबकि माइल्ड-हाइब्रिड को खारिज किया गया है, क्योंकि उनका बाजार में प्रभाव कम होता है। इसके अलावा, रेनॉल्ट रेंज एक्सटेंडर तकनीक का भी मूल्यांकन कर रहा है, जो एक छोटा आंतरिक दहन इंजन और इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन का संयोजन होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, रेनॉल्ट तीसरी पीढ़ी की डस्टर के हाइब्रिड वेरिएंट्स में 1.6-लीटर चार-सिलेंडर इंजन का उपयोग करेगा, जो दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और 1.2 केडब्ल्यूएच बैटरी के साथ जुड़ेगा, जिससे कुल 138 बीएचपी का पावर आउटपुट मिलेगा। यह तकनीक मजबूत हाइब्रिड्स की तुलना में अधिक जटिल और महंगी हो सकती है। रेनॉल्ट ने पहले इस साल दिवाली के आसपास नई डस्टर को लॉन्च करने की योजना बनाई थी।

सस्ते स्टेनलेस स्टील आयात से सुरक्षा देने कदम उठाए सरकार: उद्योग निकाय

नई दिल्ली। भारतीय स्टेनलेस स्टील विकास संघ ने स्थानीय विनिर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार से सुरक्षात्मक शुल्क जैसे कदम उठाने का आग्रह किया है। इस चुनौती से निपटने के लिए उद्योग और सरकार दोनों को मिलकर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। भारत में तैयार स्टील के बढ़ते आयात ने स्थानीय उद्योगों को असहाय बना दिया है। उच्च लागत और अनियमितता के कारण स्थानीय उत्पादकों का व्यावसायिक संसाधनों को कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। चीन से सस्ता आयात कर मार्ग से भारत में पहुंच रहा स्टेनलेस स्टील ने स्थानीय उद्योगों को कठिनाई में डाल दिया है। एक बाजार अनुसंधान फर्म के मुताबिक स्टेनलेस स्टील आयात की मात्रा में वृद्धि की दिशा में एक चिंताजनक रुख देखने को मिल रहा है। इस पर कार्यवाही के लिए होने वाले संगठन पहल से संबंधित कागजात पेश करने के लिए तैयार हैं। उद्योग के हितधारक जून में होने वाले वैश्विक स्टेनलेस स्टील शिखर सम्मेलन 2025 में इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। यहां कई उत्थानशील विचारक और निर्माताजनों को एक समायोजन में आकर्षित करना है।

ब्रिजस्टोन इंडिया ने हैदराबाद में ब्रिजस्टोन सेलेक्ट स्टोर्स का विस्तार किया

नई दिल्ली

भारत में टायर उद्योग की अग्रणी कंपनी ब्रिजस्टोन इंडिया ने हाल ही में हैदराबाद में अपने प्रमुख ब्रिजस्टोन सेलेक्ट स्टोर्स का विस्तार किया है। चार नए प्रीमियम आउटलेट्स की उद्घाटन समारोह में ब्रिजस्टोन इंडिया के एक प्रमुख अधिकारी ने उनकी इस पहल को समर्थन दिया। इस नए विस्तार के साथ हैदराबाद में ब्रिजस्टोन के कुल स्टोरों की संख्या 46 हो गई है।

देशभर में कंपनी के डीलर नेटवर्क की संख्या भी 3,200 तक पहुँच चुकी है, जिनमें से 820 सेलेक्ट प्रीमियम स्टोर्स शामिल हैं। ये स्टोर दिल्ली, गाजियाबाद, बेंगलुरु, कोल्हापुर, चेन्नई और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में स्थित हैं। ब्रिजस्टोन

हैदराबाद में ब्रिजस्टोन के कुल स्टोरों की संख्या 46 हुई

इंडिया के अधिकारी ने कहा कि हैदराबाद हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। सेलेक्ट स्टोर्स का यह विस्तार ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के साथ-साथ उनकी जागरूकता और अनुभव को भी आगे बढ़ाएगा। हमारी प्रतिबद्धता हमेशा से उच्च गुणवत्ता के साथ समाज की सेवा करने की रही है। भारत का टायर बाजार हर साल लगभग 4.4 करोड़ यूनिट्स के स्तर तक पहुँचता है, जिसमें करीब 2 करोड़ यूनिट्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (और 2.4 करोड़ यूनिट्स आफ्टरमार्केट सेगमेंट में होती हैं। ब्रिजस्टोन का आफ्टरमार्केट में लगभग 20 फीसदी बाजार हिस्सेदारी है और ओईएम सेगमेंट में यह कंपनी मारुति सुजुकी, ह्युंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टोयोटा और होंडा जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ कार्य करती है।

फिलिप्स को भारतीय कारोबार बढ़ने की उम्मीद

नीदरलैंड की एक अमरीकी कंपनी फिलिप्स ने भारत में अपने कारोबार को बढ़ाने की उम्मीद जताई है। कंपनी के क्षेत्रीय प्रमुख ने बताया कि उन्हें भारत में अपने कारोबार को दहाई अंकों में बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी के अगले पांच वर्षों में भारत में बड़ी उपलब्धियों की आशा है और उसके लिए दहाई अंकों की वार्षिक वृद्धि से मदद मिलेगी। फिलिप्स के अधिकारी ने यह भी कहा कि कंपनी न केवल स्थानीय बाजारों में बल्कि अपने वैश्विक बाजारों के लिए भी घरेलू सोर्सिंग को प्रोत्साहित कर रही है। फिलिप्स इंडिया के वित्त वर्ष 2023-24 में एकल आधार पर परिचालन राजस्व 6,000.4 करोड़ रुपये था, जो सालाना आधार पर 4.64 प्रतिशत अधिक था।

आयकर विभाग ने 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म में किए बदलाव

50 लाख तक की आय वालों को आसानी से आईटीआर दाखिल करने का मौका मिलेगा

नई दिल्ली

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में आयकर विभाग की तरफ से 2025-26 के आकलन वर्ष के लिए एक और चार आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। इन नए फॉर्मों के जरिए 50 लाख रुपये तक की कुल आय वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को आसानी से आईटीआर दाखिल करने का मौका मिलेगा। इस बड़े फैसले के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) पाने वाले व्यक्ति भी अब आईटीआर-1 फॉर्म भर सकेंगे, जो पहले आईटीआर-2 को भरना होता था। नए नियमों के अनुसार 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति, एचयूएफ, कंपनियां आदि वित्त वर्ष 2024-25 में व्यवसायिक और अन्य पेशेवर आय के लिए आईटीआर दाखिल कर सकेंगे। आईटीआर फॉर्म 1 और आईटीआर फॉर्म 4 सरल फॉर्म हैं जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम आय वाले करदाताओं के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं। सहज फॉर्म केवल उन लोगों द्वारा भरा जा सकता है जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है और जो वेतन, संपत्ति, अन्य स्रोत और कृषि से प्राप्त आय से 5,000 रुपये प्रति वर्ष तक कमाते हैं। साथ ही, सुगम फॉर्म केवल ऐसे हिंदू अविभाजित परिवारों और कंपनियों के लिए है जिनकी कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है ।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों पर विशेष योजना की शुरू

30,000 करोड़ रुपये के निवेश का रखा लक्ष्य

चेन्नई

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने बुधवार को यहां 'तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना' की शुरुआत की। राज्य सरकार की इस विशेष पहल से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का उददेश्य राज्य में 30,000 करोड़ रुपये का निवेश जुटाने और 60,000 नौकरियां सृजित करना है। तमिलनाडु ने इससे पहले मूल्यवर्धित विनिर्माण को और बढ़ावा देने तथा सेमीकंडक्टर उप-क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए सेमीकंडक्टर व उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2024 शुरू की थी।

इस नीति ने इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादन में तमिलनाडु को अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। बुधवार को जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परिवेश को मजबूत करने के इन प्रयासों को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री ने अब इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण पर केंद्रित इस विशेष योजना की शुरुआत की है। इसमें कहा गया कि तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना' केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के तहत लाभान्वित होने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए नए अवसर: एचसीएल समूह

नई दिल्ली। एचसीएल समूह ने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के बीच प्रौद्योगिकी उद्योग को सतर्क रूप से आशावादी बताया। एचसीएल समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अमेरिकी शुल्क और मुद्रास्फीति के दबाव से लागत-अनुकूलन की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं, जो भारतीय आईटी कंपनियों के लिए नए अवसर उत्पन्न कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम आशावादी हैं, क्योंकि हम इन उद्योगों के ग्राहकों के लिए काम करते हैं, जो शुल्क से प्रभावित हो सकते हैं। हमारे लिए सबसे बड़े बाजार अमेरिका है और यह यहाँ का संदेश को बचाने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने उद्योग और सुनें को ध्यान में रखते हुए यह भी कहा कि लागत अनुकूलन ही एकमात्र विकल्प है जिससे शुल्क दबावों और मुद्रास्फीति के बीच वृद्धि का मुकाबला किया जा सकता है।